दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जा

1828. **श्री राम नरेश यादव:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की कितनी भूमि अवैध कब्जे में है और इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) समयपुर बादली में जिन लोगों की भूमि अधिग्रहीत की गई थी, क्या उनको दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वैकल्पिक प्लाट दे दिए है; यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ये प्लाट कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की लगभग 6500 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है जिसमें 4718 एकड़ ऐसी भूमि शामिल है जिस पर जो यमुना नदी के किनारे किसान सहकारी समिति के अनधिकृत दखल में हैं तथा जिसे न्यायालय से स्थगनादेश के कारण हटाया नहीं जा सका । शेष भूमि पूरी दिल्ली में छितरी हुई है तथा उस पर भारी अतिक्रमण है दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इनमें से अधिकांश को हटाने के लिये बेदखली कार्यक्रम का संबंध समय-समय पर पर्याप्त विकसित प्लाटों की उपलब्धता से है ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 102 व्यक्तियों को पहले ही वैकल्पिक प्लाट आवंटित कर दिये हैं तथा 125 व्यक्तियों को दिसम्बर, 1988 में वैकल्पिक प्लाटों की पेशकश की गई है । 547 व्यक्ति अभी भी आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं । जैसे प्लाट उपलब्ध होंगे वैसे ही इन व्यक्तियों को भी उनकी वरिष्ठता के अनुसार प्लाट आवंटित कर दिये जायेंगे ।

Technology from West Germany for rapid transport system in Delhi

1829. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of URBAN DE VELOPMENT be pleased to state:

(a) whether West Germany has offered latest technology for rapid transit system in the urban areas and if so, the details thereof; and

(b) the action taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SINGH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Policy for edible oils and pulses to cut down import

1830. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to formulate an edible oil and pulses policy to cut down import; and

(b) if so, the salient features therof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI HARI KRISHNA SHASTRI): (a) On the recommendations of the Technology Mission on Oilseeds, the